

उच्च शिक्षा... एआईयू के अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण में खुलासा ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के सामने पिछड़ जाते हैं भारतीय विवि

जब भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक मानकों पर खरा उतरने की बातें होती हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के टॉप-100 विश्वविद्यालयों के सामने भारतीय विश्वविद्यालय कहीं नहीं ठहरते। ये बातें एक अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण में सामने आईं। इसके पीछे कई कारण गिनाए जाते हैं। इनमें प्रति छात्र प्रति वर्ष औसत खर्च कम होना, संसाधनों का अभाव, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में अव्वल आने की चुनौतियां और प्रतिकूल वातावरण के बीच बेहतर कर दिखाने का दबाव प्रमुख है। हालांकि इससे राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने देश के टॉप-20 विवि को 10,000 करोड़ रुपए का बजटीय अनुदान देने की घोषणा की है, पर ये राशि टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के सामने टोकन मनी के समान ही है। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि अगर ये पैसे देश के टॉप-20 विवि को मिल भी गए तो क्या वे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को टक्कर दे पाने में सक्षम हो पाएंगे?

ये है इसकी वजह

एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के महासचिव फुरकान कम्मर ने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्लेषण में इस बात का खुलासा किया कि टॉप 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हर लिहाज से भारतीय विश्वविद्यालयों से बेहतर साबित होते हैं।

चाहे बात बजटीय सहायता, शैक्षिक स्वायत्तता, छात्र-शिक्षक अनुपात, कानूनी बंधनों में से कुछ भी क्यों न हो। हर मामले में हमारे उच्च शिक्षण संस्थान कमजोर नजर आते हैं। चौकाने वाली बात यह है कि अमरीका में पढ़ाई के मामले में जहां दुनिया के देशों के छात्रों की संख्या में कमी आई है वहीं भारतीय छात्रों की संख्या में 12 फीसद से ज्यादा का इजाफा हुआ है। जबकि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, इंडोनेशिया जैसे देशों के छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। वहां के छात्र अब दूसरों देशों की ओर रुख करने लगे हैं।



राजस्व स्रोत

छात्रों से ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को बतौर फीस 30 फीसद व बाकी का पैसा अन्य स्रोत से मिलता है। जबकि भारतीय विवि कम बजटीय सहायता पर निर्भर होते हैं।

छात्र-शिक्षक अनुपात

संस्थागत स्वायत्तता

विदेशी यूनिवर्सिटीज को फंड हासिल करने के लिए कंसल्टेंसी, तकनीक ट्रांसफर, औद्योगिक इकाईयों से कॉट्रैक्ट करने जैसे मामलों में अकादमिक स्वायत्तता हासिल है। जबकि भारतीय संस्थानों को इस तरह की स्वायत्तता हासिल नहीं है। इसके बदले भारत में विवि को सरकारी बंधनों के तहत काम करना होता है।

रैंक निर्धारण

भारत में रैंकिंग का निर्धारण एमएचआरडी की ओर से किया जाता है। इसका नुकसान यह होता है कि स्वायत्तता प्राप्त आईआईटीज की ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों को बाहर कर दिया जाता है। जबकि भारतीय विश्वविद्यालयों को यूजीसी के नियमों और उनके सुपरविजन में काम करना होता है।

20 विवि के लिए 10,000 करोड़

टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को फाइट देने के लिए केंद्र सरकार ने 20 विश्वविद्यालयों को 10,000 करोड़ का बजट देने की घोषणा की है। इनमें 10 सरकारी और 10 गैर सरकारी विश्वविद्यालय होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि इस धनराशि के बावजूद हम कहां होंगे।



बेहद कम है भारत का खर्च

कय शक्ति के लिहाज से देखें तो 4.8 लाख रुपए में जो सुविधा भारतीय छात्र उठा लेते हैं उन्हीं सुविधाओं का लाभ उठाने में अमरीका में छात्रों को 18.2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस लिहाज से भी देखें तो टॉप-100 विश्वविद्यालयों के छात्र भारत के टॉप 10 विवि की तुलना में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं।

खर्च प्रति छात्र

4.8 लाख

टॉप 10 भारतीय संस्थानों का प्रति वर्ष औसत खर्च

11 करोड़

टॉप 100 ग्लोबल विवि में प्रति वर्ष खर्च

भारत में सबसे ज्यादा खर्च

भारत में आईआईएससी बेंगलूरु के छात्रों पर औसत खर्च प्रति छात्र प्रति वर्ष 11.35 लाख रुपए है, जो देश में सबसे ज्यादा है। आईआईटी गुवाहाटी में 6.67 लाख, आईआईटी मुम्बई में 6.06 लाख, आईआईटी मद्रास में 5.93 लाख और आईआईटी कानपुर में 5.51 लाख औसत खर्च है।

हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी प्रिंसटन, कोलंबिया और शिकागो जैसे टॉप-100 यूनिवर्सिटी में छात्र-शिक्षक अनुपात 1:10 के करीब है। भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में यह दर 1:16 है।

आईआईटी दिल्ली (1:13), मद्रास (1:15) व आईआईएससी बेंगलूरु (1:8)